इकाई 13 राज्य, नागरिक समाज और समुदाय

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देष्य
13.1 प्रस्तावना
13.2 अर्थ और संबंध
13.2.1 राज्य और नागरिक समाज
13.2.2 लोकतंत्र और नागरिक समाज
13.3.3 समुदाय और नागरिक समाज
13.3 नागरिक समाज के चारित्रिक लक्षण
13.4 सारांष
13.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें
13.6 बोध प्रष्नों के उत्तर

13.0 उद्देष्य

इस इकाई में आप पायेंगे कि नागरिक समाज के सिद्धांत और राज्य व समुदाय के साथ उसका संबंध। इस इकाई को पढ़ लेने के बाद आप इस योग्य होंगे कि :

- नागरिक समाज के अर्थों और सिद्धांतों को जान सकें;
- उसकी उत्पत्ति के कारण समझ सकें;
- नागरिक समाज और समुदाय के बीच संबंध पूरी तरह समझ सकें; तथा
- लोकतंत्र के लिए नागरिक समाज के महत्त्व का मूल्यांकन कर सके।

13.1 प्रस्तावना

राज्य, नागरिक समाज और समुदाय संबंधी अवधारणाएँ सामाजिक विज्ञानों में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, खासकर राजनीति-विज्ञान संबंधी की प्रकृति में। लोकतंत्र, अधिकार, नागरिकता, सामाजिक पूँजी आदि विषयक कोई भी बहस इन तथ्य घटनाओं से ही जुड़ी होती है। विषिष्ट और सार्वत्रिक अधिकारों के बीच क्या संबंध है? नागरिक जन अपने अधिकारों का उपभोग करने में, बुनियादी तरक्की लाने में किस प्रकार सक्षम हैं, उस भूमिका पर निर्भर करता है जो कि राज्य, नागरिक समाज और समुदाय अदा करते हैं। लोकतंत्र व विकास के प्रति उनके औचित्य विषयक विरोधीभासी मत हैं। इस इकाई में आप इन अवधारणाओं व उनके बीच संबंधों को समझेंगे।

13.2 अर्थ और संबंध

13.2.1 राज्य और नागरिक समाज

राज्य के अर्थ और प्रकृति के विषय में आप इकाई 11 में पहले ही पढ़ चुके हैं। हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। इस भाग में हम सीधे नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंधों की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। राज्य राजनीति-सिद्धांत में उल्लिखित सबसे महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य समाज की अन्य संस्थाओं से भिन्न होता है, यथा सरकार, नागरिक समाज, समुदाय राष्ट्र आदि से। उदारवादी परम्परा

के अनुसार, राज्य से अपेक्षा होती है कि वह समाज के विकास में आने वाली बाधाएँ दूर करे, साथ ही समाज-कल्याण हेतु उपाय भी मुहैया कराये। दूसरी ओर, मार्क्सवादी परम्परा राज्य को धनी वर्गों के अन्धभक्त के रूप में देखती है। नागरिक समाज की अवधारणा को लोकप्रियता मिलने के साथ ही नागरिक समाज से राज्य के संबंध ने फिर से राजनीति-सिद्धांत संबंधी बातचीत में एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

अभी हाल में, खासकर 1980 के दषकोपरांत, नागरिक समाज की अवधारणा ने राजनीति-सिद्धांत विषयक संलाप में एक विषेष स्थान बनाया है। विकास सामाजिक बदलाव पर अभिलक्षित अपने संगठनों, प्राधार व विचारधारा को लेकर नए सामाजिक आन्दोलनो के उदय तथा पूर्वी यूरोप और पूर्व-सोवियत संघ में विकास ने नागरिक समाज में रुचि जगायी है। ये दोनों घटनाक्रम राज्य की विष्वसनीयता और समांतर सत्ता-केन्द्रों के उद्‌गमन में ह्वास (erosion) को दर्षाते हैं। नागरिक समाज की उत्पत्ति क्रम-विकास काफी कुछ उसके राज्य के साथ संबंध की वजह से हुआ है। जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंध की प्रकृति राजनीति-सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

नागरिक समाज की ओर हाल ही में गया ध्यान सामाजिक आन्दोलन उद्‌भेदन (eruption) अथवा राज्य के जन-असंतोश में भी देखा जा सकता है। नागरिक समाज वह स्थान है, जो समुदाय और राज्य के बीच होता है। इसका प्रतिनिधित्व उन संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों के लोगों, पार्षद विद्वानों, बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाता है जो समाज में लोकतंत्र की स्थापना हेतु प्रयास करते रहते हैं। चूँकि नागरिक समाज संस्थाएँ राज्य और समुदाय के बीच स्थित होती हैं और राज्य का विरोध करती हैं, उन्हें आमतौर पर ऐसी संस्थाएँ कहा जाता है जो राज्य से दूर होती हैं। नागरिक समाज को संपूरक के साथ-साथ कभी-कभी राज्य संस्थाओं के लिए एक अनुकल्प के रूप में माना जाता है। सभ्य समाज के निर्माण का आधार धर्मनिरपेक्ष होता है। जाति और नातेदारी अनुबंध, धर्म अथवा जनजातीय संघटन आदि नागरिक-समाज निर्माण के आधार नहीं होते। नीरा चंधोक के अनुसार, मूल संबंधों पर आधारित ये संगठन वस्तुतः ''नागरिक समाज विरोधी'' आन्दोलन होते हैं।

इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यह गौर करना जरूरी है कि अठारहवीं शताब्दी तक पुरानी यूरोपीय परम्परा में, राज्य और नागरिक-समाज शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते थे। डोमिनीक कोला ने नागरिक समाज की अवधारणा का इतिहास खोजा और पाया कि यह 16वीं व 17वीं शताब्दियों में अतिधर्मान्धता के खिलाफ एक अवधारणा के रूप में इस्तेमाल की जाती रही। उस ज़माने में, राज्य ही था जो एक अधिकारों की संस्था के रूप में चर्च का विरोध करता था। इसका मतलब कि राज्य एक नागरिक समाज के रूप में कार्य करता था अथवा उनके बीच कोई भेद नहीं था। नागरिक समाज राज्य का ही एक पहलू था। (जो कि चर्च के खिलाफ था)। यह वस्तुतः आने वाले समय में ही हुआ कि इनको दो भिन्न सत्ताओं के रूप मे जाना जाने लगा।

यह तथ्य कि क्या कोई नागरिक समाज होता है अथवा नहीं, उस संबंध की प्रकृति पर निर्भर करता है जो वह राज्य के साथ रखता है। इससे राजनीति-सिद्धांत में अनेक प्रष्न उठे। राज्य नागरिक समाज से कनिष्ठ है अथवा वरिष्ठ? क्या इनमें से एक दूसरे के बगैर रह सकता है? वे एक दूसरे के हितों के प्रति विद्वेशी होते हैं अथवा समर्थक? नागरिक समाज के मुकाबले राज्य किसके हित का काम करता है? मूल रूप से चार पहलू हैं, जो राजनीति-सिद्धांत में इन प्रष्नों से वास्ता रखते हैं – तोकेवियन, लॉकियन, हेगेलियन और मार्क्सवादी। तॉकवि अपनी पुस्तक – *डेमोक्रेसी इन अमेरिका* – में अमेरिका में लोकतंत्र की विद्यमानता और फ्रांस में उसके अभाव के लिए कारणों का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। वह

पाते हैं कि दोनों देषों में यह राज्य का स्वभाव ही है जिस पर लोकतंत्र की विद्यमानता अथवा उसका अभाव निर्भर करता है।

यह अमेरिका में विद्यमान था, क्योंकि वहाँ एक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य ने लोगों की संस्थाओं के निर्माण को अनुमति दी थी, जिसने उनके बीच परस्पर विष्वास की विद्यमानता को इंगित किया। जैसा कि आप अगले भाग में पढ़ेंगे, संस्था संबंधों का बनना एक नागरिक समाज का संकेत है। नागरिक समाज बदले में लोकतंत्र को प्रतिबिम्बित करता है। फ्रांस में, तॉकवि कहते हैं, कि अमेरिका से भिन्न, राज्य की स्वेच्छाचारी शासन अथवा अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति के कारण वहाँ नागरिक संस्था अथवा समाज का अभाव था।

इंग्लैंड के 17वीं सदी के विचारक जॉन लॉक के उदाहरण में, राज्य व नागरिक समाज के बीच संबंध को इन दो सत्ताओं के बीच संबंधों के लिहाज से देखा जा सकता है –□ प्राकृत अवस्था में और प्राकृत-अवस्था उपरांत। एक सामाजिक संविदावादी विचारक के रूप में, लॉक का विष्वास था कि राज्य एक अनुबंध का परिणाम है, जो उन व्यक्तियों के बीच किया गया था, जो प्राकृत अवस्था में रह रहे थे। वे कुछ निष्चित अधिकारों का उपयोग करते थे, जो उनके लिए प्रकृति द्वारा आवष्यक बनाए गए थे। परंतु ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं होता था जो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके अथवा उनके कार्य-व्यापारों को नियमित कर सके। इस प्रकार का प्राधिकरण राज्य ही हो सकता था, जो उस सामाजिक अनुबंध से जन्मा था जो लोगों ने एक दूसरे से किया था। इस अनुबंध के माध्यम से, प्राकृत अवस्था वाला राजनीतिक समाज एक नागरिक समाज में बदल गया था। लॉक, दरअसल, नागरिक और राजनीतिक को अदल-बदल कर प्रयोग करते हैं। लॉक के नागरिक और राजनीतिक समाज के बीच भेद करना कठिन है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि लॉक के अनुसार नागरिक समाज उन अधिकारों को सुनिष्चित करने के लिए ही बनाया गया था, जो प्राकृत अवस्था में पहले ही प्राप्य थे। जैसा कि नीरा चन्धोक कहती हैं, लॉक का ''राजनीतिक समाज'' प्राकृत के मुकाबले एक ''नागरिक अवस्था'' था। नागरिक अथवा राजनीतिक समाज उन अधिकारों की रक्षार्थ बनाया गया था, जो लोगों ने प्राकृत अवस्था से उत्तराधिकार में प्राप्त किए थे। (देखें गुरप्रीत महाजन इसकी व्याख्या किस प्रकार करती हैं)।

जर्मन दर्षनिक हेगेल ने सबसे ज़्यादा क्रमबद्ध रूप से नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंध का अध्ययन किया है। अपनी पुस्तक 'फिलौसॅफ़ि ऑफ राइट्स' में हेगेल नागरिक समाज को नैतिक जीवन के अवसरों में से एक मानते हैं, अन्य दो हैं परिवार और राज्य। नागरिक समाज को परिवार और राज्य दोनों से भिन्न माना जाता है। परिवार में, हेगेल का दावा है, विषिष्ट हित एक नैसर्गिक एवं अचिंतनषील एकता में अनुभवातीत होते हैं और सदस्यों के बीच कार्य-सम्पादन, प्रेम और गंभीर दिलचस्पी, द्वारा निष्चित होता है; जबकि राज्य में, व्यापकता को संस्थागत किया जाता है, क्योंकि नैतिक जीवन का सर्वोच्च रूप 'नैतिक विचार की वास्तविकता' ही है। नागरिक समाज, तुलनात्मक रूप से, विषिष्टता का, अपनी निजी आवष्यकता पूर्ति की चिंता में डूबे स्वयं प्रयासरत व्यक्ति का, क्षेत्राधिकार है। इस अवस्था में, परिवार का लोकाचार, यथा नैसर्गिक प्रेम और परहितपरता, अनेकीकृत हो जाता है; परन्तु समान रूप से, यहीं व्यापकता का सिद्धांत, जिसको कि राज्य मूर्त रूप देने आता है, एक भ्रूणीय रूप में पाया जाता है।

परिवार की अंचितनषील चेतना से चैतन्य नैतिक जीवन के बीच एक महत्त्वपूर्ण चरण के रूप में नागरिक समाज ऐसा स्थल बन जाता है, जहाँ इस हेगेलियन दार्षनिक चिंता की विषिष्टता द्वारा व्यापकता मध्यस्थ हो– का अनुभव किया जा सकता है।

मार्क्सवादी परम्परा में नागरिक समाज धनी वर्गों, पूँजीवादी वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। तथापि, नागरिक समाज के लिहाज से मार्क्सवादी परम्परा में दो दृष्टिकोण हैं। एक है, पारम्परिक दृष्टिकोण (Classical Approach)। यह मार्क्स से संबंधित है, जिन्होंने नागरिक-समाज विषयक हेगेलियन पहलू को उत्तराधिकार रूप में प्राप्त किया, परन्तु उन्होंने स्वयं व्यवस्था पर परिप्रेक्ष्न करने हेतु विष्लेषण को आगे बढ़ाया। मार्क्स के अनुसार, यह मात्र पृष्ठभूमि नहीं है, जहाँ एक व्यक्ति का निहित स्वार्थ दूसरे व्यक्ति के निहित स्वार्थ को पूरा करता है; यह ऐसा स्थान है जहाँ अनावष्यक श्रम का विनियोजन होता है। ऐतिहासिक चरण से आगे जरूर बढ़ना चाहिए। परन्तु मार्क्स, हेगेल से भिन्न, इस संभावना से इंकार करते थे कि कोई वर्तमान संस्था यह काम कर सकती है। नागरिक समाज को स्वयं में से यह नया अभिकरण खोजना चाहिए, ताकि वह अहंकार व स्वार्थ, शोषण एवं मानवता से आगे बढ़ सके। और इस क्षेत्र की प्रकृति के मद्देनज़र इस परिवर्तन को क्रांतिकारी होना पड़ता है। केवल तभी व्यक्ति को समाज और राज्य से जोड़ा जा सकता है। क्रांतिकारी परिवर्तन नागरिक समाज को विनीत बनाने का संगठनकारी सिद्धांत बन जाता है।

मार्क्सवादी आदर्ष में दूसरे स्थान पर है ग्राम्सियन परम्परा। ग्राम्सी, हालाँकि अर्थव्यवस्था समेत, निजी अथवा गैर-राज्यीय क्षेत्र का संदर्भ लेने के लिए 'नागरिक समाज' का प्रयोग करते हैं, नागरिक-समाज संबंधी उनका चित्रण मार्क्स के वर्णन से बहुत भिन्न है। ग्राम्सी का मुख्य प्रस्ताव यह है कि राज्य को नागरिक समाज के बोध के बिना नहीं समझा जा सकता है। ग्राम्सी के अनुसार, नागरिक समाज महज कोई वैयक्तिक आवष्यकताओं का क्षेत्र नहीं है वरन् संगठनों का क्षेत्र है, और युक्तियुक्त आत्म-नियमन व स्वतंत्रता की संभावना रखता है। ग्राम्सी इसके जटिल संगठन पर ज़ोर देते हैं, क्योंकि 'जीवों की समष्टि' को आमतौर पर 'निजी' कहा जाता है जहाँ आधिपत्य और 'स्वैच्छिक सहमति' सुव्यवस्थित रूप में होते हैं। जबकि मार्क्स राज्य और नागरिक समाज के बीच अलगाव पर ज़ोर देते हैं, ग्राम्सी यह तर्क देते हुए दोनों के बीच अंतर्सम्बन्ध पर ज़ोर देते हैं कि हाँ राज्य शब्द के साधारण, संकीर्ण प्रयोग का अभिप्राय सरकार से हो सकता है, संकुचित रूप से सरकार के रूप में समझे जाने वाले राज्य को अवपीड़क राज्य-तंत्र द्वारा अभिपुष्ट प्रबल वर्ग के आधिपत्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। ग्राम्सी के अनुसार, राजनीतिक समाज वह स्थान है, जहाँ राज्य का अवपीड़क तंत्र कारागारों, न्याय-प्रणाली, सषस्त्र सेनाओं व पुलिस में संकेन्द्रित रहता है। नागरिक समाज वह 'स्थान' है जहाँ राज्य षैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पद्धतियों व अन्य संख्याओं के माध्यम से सत्ता के अदृष्य, अमूर्त व जटिल रूपों को प्रवलित करने के लिए काम करता है। वस्तुतः राज्य की अवज्ञा करने को ग्राम्सी द्वारा नागरिक समाज के आत्म-नियामक सहजगुणों के सम्पूर्ण विकास संबंधी शब्दों में पुनर्परिभाषित किया गया है।

इसका सबसे पहले जान लॉक के लेखों में उल्लेख किया गया था। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, उन्होंने बताया कि यह नागरिक समाज प्राकृत अवस्था के एक नागरिक समाज में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप उभरा। उन्होंने नागरिक समाज को प्राकृत अवस्था और राजनीतिक समाज से अलग माना। यह नागरिक समाज अनुबंध के परिणामस्वरूप उभरे लोक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानूनों के मार्फत राजनीतिक समाज में बदल जाता है। नागरिक समाज एक (राजनीतिक) समाज है, जहाँ व्यक्तियों के अधिकारों को प्राथमिकता मिलती है। नागरिक समाज इस अर्थ में अन्य संस्थाओं से भिन्न होता है कि पूर्ववर्ती से भिन्न, यह व्यैक्तिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है। इसका स्थान राज्य से बाहर नहीं है, बल्कि यह (नागरिक समाज) राज्य की विद्यमानता से ही उभरा है। इसका मतलब कि वे लोग जो प्राकृत अवस्था में रह रहे थे, जीवन-स्वतंत्रता व स्वामित्व के नैसर्गिक अधिकारों का उपभोग कर रहे थे, एक आम जन-प्राधिकरण के तहत एक सामाजिक अनुबंध में

शामिल हुए, जो कि एक ऐसे न्यायोचित समाज की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ हुआ था, जिसमें हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जा सकती थी। इस लोकप्राधिकरण को जनता अथवा नागरिक समाज विषयक कानून बनाने का अधिकार होता है। यह नागरिक-समाज प्राकृत अवस्था से भिन्न था, जहाँ लोग समान नैसर्गिक अधिकारों का उपभोग करते थे परन्तु उन्हें दोशियों को दण्डित करने का कोई अधिकार नहीं था। सामाजिक अनुबंध तैयार किए जाने से पहले समाज एक अनागरिक समाज के रूप में विद्यमान था। इस प्रकार, नागरिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

उन्नीसवीं शताब्दी में जब हेगेल ने नागरिक समाज के विचार का विस्तार किया, लॉक के विचार को लगभग दो सदियाँ बीत चुकी थीं। परन्तु इन दो विचारकों द्वारा अभिकल्पित अवधारणाओं के बीच भेद थे। लॉकियन व्यवस्था में खास महत्त्व, व्यक्तियों के विषिष्टतावादी अथवा आत्मपरक अधिकारों को दिया गया है। वह विषिष्टतावादी अथवा व्यक्तिनिष्ठ अधिकारों एवं सार्वभौम अधिकारों के बीच संबंधों के विषय में कुछ भी नहीं कहते। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, हेगेल दूसरी ओर यह मानते हैं कि कोई नागरिक समाज केवल तभी अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है, जब समाज में नैतिक व्यवस्था हो। नैतिक व्यवस्था का, उनके अनुसार, अर्थ है व्यक्तिपरक और सार्वत्रिक कानूनों के सामन्जस्य में अस्तित्व। व्यक्तिपरक कानून समुदायों में जन्म लेते हैं, और उस समुदाय की विषिष्टता से ताल्लुक' रखते हैं, यथा उसकी परम्पराओं, रीति रिवाज, समुदाय में प्रत्येक सदस्य का स्थान, बड़ों से उसके संबंधों, पुरोहितों, महिलाओं की स्थिति, आदि से। ये विषिष्टतावादी होते हैं। दूसरी ओर, सार्वत्रिक कानून राज्य के उन कानूनों से संबंध रखते हैं, जो उस राज्य के लिखित अथवा अलिखित संविधान में प्रतिष्ठापित होते हैं। ये कानून व्यक्तियों के अधिकार संबंधी सार्वभौम सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, यथा समानता, स्वतंत्रता, स्वामित्व एवं बंधुत्व। यदि सार्वत्रिक और व्यक्तिपरक अधिकार एक साथ अस्तित्व में होते हैं, कोई भी उनके बीच व्याप्त भेदों के बावज़ूद दूसरे को अस्वीकार नहीं करता है। वस्तुतः तभी समाज में एक नैतिक व्यवस्था कायम होती है। इसका, हेगेल की नजर में, अर्थ है कि सह-अस्तित्व की ऐसी व्यवस्था में नागरिक समाज कायम रहता है।

नागरिक समाज की अवधारणा को बीसवीं सदी में फिर से लोकप्रियता मिल गयी। 1980 के दषक में पूर्व-सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के विघटन ने इस अवधारणा में रुचि फिर से जगाई। राज्य की विफलता के कारण उसमें विष्वास खोने से नागरिक समाज में रुचि फिर से जगी। राज्य की धारणा टूटने लगी, ज्यादा सटीक रूप से, बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में इसको राज्य के एक विकल्प के रूप में देखा जाने लगा।

साथ ही, चूँकि मार्क्सवादीजन नागरिक समाज को अन्धभक्त और असमान एवं विभेदकारी वर्ग-संबंधों को बढ़ाने में योगकारी मानते हैं, गैर-मार्क्सवादी जन नागरिक समाज को राज्य की विफलता हेतु एक रामबाण मानते हैं। नागरिक-समाज संबंधी गैर-मार्क्सवादी आदर्ष, जो इसे राज्य के एक विकल्प के रूप में देखते हैं, लोकतंत्र के सहकारी प्रतिरूप से संबंध रखते हैं।

बोध प्रष्न 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये इकाई का अंत देखें।

1) नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं? राज्य के साथ इसके संबंध पर सूक्ष्म दृष्टि डालें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) नागरिक समाज संबंधी अवधारणा का क्रम-विकास प्रस्तुत करें।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13.2.2 लोकतंत्र और नागरिक समाज

लोकतंत्र और नागरिक समाज एक दूसरे से अवियोज्य (inseparably) रूप से जुड़े हैं। एक स्वस्थ उदारवादी लोकतंत्र को जीवट और ऊर्जा से भरपूर नागरिक समाज के सहयोग की आवष्यकता होती है। जैसा कि पूर्व भागों में उल्लेख किया गया, लोकतंत्र-नागरिक समाज अन्तर्संबंध विषय-विषेष का आधार तॉकवि के अमेरिकी राजनीति विषयक उत्कृष्ट लेखों में देखा जा सकता था।

हाल के वर्षों में अनेक विद्वान हुए हैं, जिन्होंने इस लोकतंत्र-नागरिक समाज संबंध को लोकतंत्र के विभिन्न प्रतिरूपों में विकसित किया है। इस प्रकार एक प्रतिरूप है, 'लोकतंत्र का संस्थागत प्रतिरूप' जैसा कि सुनील खिलनानी, पॉल ट्रस्ट एवं बेंजामिन बार्बर द्वारा विकसित किया गया। उनके अनुसार, सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही नागरिक समाज के निर्माण का आधार है। सत्ता की विकेन्द्रीकृत इकाइयाँ न्यास, संस्था व लोकतंत्र की ओर अभिनत होती हैं। परन्तु लघुतर समुदायों के निर्माण का आधार सर्वधर्म समभावी समानता है, न कि आरोप्य (ascriptive)। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक राज्य के केन्द्रीकृत प्राधिकार के आलोचक हैं, जिसको कि वे बहुत अधिक प्रभावषाली मानते हैं। वे अपनी उम्मीदें समुदायों अथवा पष्चिमी लोकतंत्रों में विकेन्द्रीकरण से जोड़ते हैं। नागरिक समाज का परिप्रेक्ष्य उस साहित्य से जुड़ा है, जो समाजवादी समाजों के पतन के चलते, खासकर पूर्वी यूरोप में, उद्‌गमित हुआ। यहाँ, नागरिक समाज सर्वसत्तात्मक राज्य के मुकाबले उभरकर आया। व्यक्तिजनों के अधिकार, जिनका सर्वसत्तात्मक राज्य-व्यवस्था के दौरान अतिक्रमण किया गया था, नागरिक समाज में सुरक्षा प्रदान किए जाएँगे, ऐसा सोचा गया।

नागरिक समाज की विद्यमानता किसी समाज में लोकतंत्र के विस्तार क्षेत्र को भी इंगित करती है; यथा औपचारिक लोकतंत्र जैसे चुनाव, बहुदलीय प्रणाली अथवा एक लोकतांत्रिक संविधान। इसी के साथ, यहाँ इसका अर्थ लोकतांत्रिक प्रतिमानों व मूल्यों की विद्यमानता भी होता है, जैसे एक दूसरे की संस्कृति व दृष्टिकोणों की सहिष्णुता के साथ मतभेदों का

सहअस्तित्व। गैलनर के अनुसार, लोकतंत्र की सांस्थानिक धारणा नागरिक समाज की सांस्थानिक धारणा के मुकाबले कम बोधगम्य है। नागरिक समाज विवाद और बहस का एक अखाड़ा है। नीरा चन्धोक कहती हैं, कि नागरिक समाज एक ऐसा स्थल है, जहाँ व्यक्तिजन एक दूसरे के सहयोग से अपने प्रतिमान तय करते हैं। यह उनके जीवन में बसता है, जो अपने पर राज्य थोपे जाने पर आपत्ति करते हैं। वे राज्य से अपने सवालों को जवाब माँगते हैं। नागरिक समाज का हर समूह अपनी निर्दिष्टता, यथा संस्कृतिक को कायम रखने का हकदार होता है। जो स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांतों पर आधारित होती है। मनोरंजन मोहन्ती के अनुसार, नागरिक समाज संगठनों को ''प्राणी समाज'' कहा जा सकता है, क्योंकि ये संस्थाएँ राज्य पर संदेह करती हैं और एक समतावादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने के लिए कठोर प्रयास करती हैं।

नव-तॉकवियन लोगों की एक नयी पीढ़ी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं रॉबर्ट पुट्नम, ने 1990 के दषक से लोकतंत्र की आधारषिला के रूप में नागरिक समाज की अवधारणा को पुनरुज्जीवित किया। पुटनम ने 'सामाजिक पूँजी' (social capital) नामक एक अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, जिसका अर्थ है ''सामाजिक संगठनों के अभिलक्षण, यथा आस्था, प्रतिमान और नेटवर्क''। लोकतंत्र व सामाजिक पूँजी के बीच संबंध उत्तर व दक्षिण इटली भर में स्थानीय सरकारों के विभिन्न कार्यनिष्पादन संबंधी पुट्नम के प्रसिद्ध अध्ययनों में से एक से निकला है। इनकी पुस्तक का दावा है कि उत्तर इटली ने आमतौर पर दक्षिण इटली की अपेक्षा बेहतर संस्थागत कार्यनिष्पादन को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि यहाँ परिस्थितियाँ ऐतिहासिक रूप से उन नागरिक मामलों में अधिक जन-भागीदारों से जुड़ी हैं, जो समाज में बेहतर अन्तर्वैयक्तिक एवं सांस्थानिक विष्वास की उपलब्धता से स्वयं उत्पन्न हुई।

बोध प्रष्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये इकाई का अंत देखें।

1) लोकतंत्र का संघीय स्वरूप क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) नागरिक समाज विषयक रॉबर्ट पुट्नम के विचारों पर चर्चा करें।

.....

.....

.....

.....

.....

13.2.3 समुदाय और नागरिक समाज

समुदाय आदिकालीन तथ्यों पर आधारित संबंधों से जुड़े लोगों का एक समूह है, यथा, धर्म, नाते, पारिवारिक बंधन, जाति, आदि से जुड़े लोगों का समूह। ये व्यक्तियों के लिए नियम तय करते हैं, जो समुदाय का निर्माण करते हैं। व्यक्तियों व नागरिकों के अधिकारों के बारे में समुदाय के नियमों की प्रकृति राजतंत्र व समाज की प्रकृति को दर्षाती है। समुदाय के नियम एकनिष्ठवादी होते हैं, जबकि राज्य के नियम सर्वमुक्तिवादी होते हैं। नियमों की दो श्रृंखलाओं के बीच यदि कोई विवाद होता है, तो राज्य-व्यवस्था की लोकतांत्रिक इमारत ढह जाती है। परन्तु यदि दूसरी ओर, एक समाज में व्यक्तियों के अधिकार राज्य के अधिकारों के अनुरूप होते हैं, राज-व्यवस्था लोकतांत्रिक गुण-दोशों का प्रतिनिधित्व करती है। समुदाय राज्य और नागरिक समाज के बीच स्थित होता है। समाज के भीतर व्यक्तियों – महिलाओं, अलाभांवित समूहों, अल्पसंख्यकों आदि – के लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति राज्य, नागरिक समाज और समुदाय संबंधी तीनों ही संस्थाओं की प्रकृति पर निर्भर करती है।

समुदाय और नागरिक समाज के बीच भेद विषयक समाजषास्त्रीय बहस फर्डीनैंड टोनीस की पुस्तक में अपने विषुद्धतम, सुड़ौलतम और जटिलतम रूप में दिखाई पड़ती है। टोनीस ने इनको 'यथार्थ अथवा सहज जीवन' तथा 'काल्पनिक अथवा यांत्रिक प्राधार' – जमेन्षाफ (Gemeinschaft) तथा जसैलषाफ (Gesellschaft) कहा। टोनी के शब्दों में, जमेन्षाफ पुराना होता है; जसैलषाफ नया होता है। ग्रामीण जीवन में लोगों के बीच समुदाय ज़्यादा सषक्त और ज़्यादा जीवन्त होता है; यही एक साथ रहने का टिकाऊ और खरा ढंग है। जमेन्षाफ के मुकाबले, जसैलषाफ (समाज) अस्थायी और सतही होता है। तदनुसार, जमेन्षाफ (समुदाय) को एक जीवित प्राणी के रूप में समझा जाना चाहिए, जसैलषाफ को एक यांत्रिक समूह और एक पुरातन कला या षिल्प रचना के रूप में।

एक लेख 'इन सर्च ऑफ सिविल सोसाइटि' में सुदीप्तो कविराज दो द्वैदाष्यों (dichotomis) के बीच एक संबंध बताते हैं – एक ओर राज्य और नागरिक समाज के बीच और दूसरी ओर नागरिक समाज और समुदाय के बीच। तृतीय- विष्व राजनीति संबंधी अनेक प्रकार के विष्लेषणों में इन दो अलग-अलग तर्कों के बीच महत्त्वपूर्ण संबंध हैं। यह दावा किया गया है कि एक आधुनिक संवैधानिक राज्य के ठीक संचालन के लिए एक विषिष्टता आवष्यक होती है, न सिर्फ समाज में राज्य व अन्य संगठनों के बीच, बल्कि जसैलषाफ जैसे सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले गैर-राज्यीय संगठन में भी।

13.3 नागरिक समाज के चारित्रिक लक्षण

नागरिक समाज के इतने विविध विष्लेषण हैं कि यह शब्द भ्रामक लगने लगता है। अतः नागरिक समाज के लक्षणों पर एक अभिदृष्टि विषय को पूरी तरह समझने में मदद कर सकती है। डायमण्ड के अनुसार, नागरिक समाज के लक्षण इस प्रकार ब्यौरेवार प्रस्तुत किए जा सकते हैं :

प्रथम, नागरिक समाज ही संगठित सामाजिक जीवन का कार्यक्षेत्र है, जो कि सार्वजनिक स्वैच्छिक, स्वयं-उत्पन्न, कम-से-कम अंषतः स्वयं-समर्थक, राज्य से स्वतंत्र और एक कानूनी व्यवस्था अथवा साझा नियमों की श्रृंखला द्वारा बाध्य होता है। यह आमतौर पर ''समाज'' से इस बात में भिन्न होता है कि इसमें एक सार्वजनिक क्षेत्र में सामूहिक रूप से काम करने वाले नागरिक शामिल होते हैं।

दूसरे, नागरिक समाज निजी उद्देष्यों की बजाय सार्वजनिक उद्देष्यों से संबंध रखता है। यह निजी क्षेत्र और राज्य के बीच खड़ी एक मध्यवर्ती दृष्य-घटना है। इस प्रकार, यह संकुचित समाज को बहिष्कृत करता है : वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन तथा अन्तर्मुखी सामूहिक कार्य; और यह आर्थिक समाज को बहिष्कृत करता है : वैयक्तिक व्यापार-समवायों के लाभार्जन करते उद्यम।

तीसरे, नागरिक समाज किसी न किसी तरह राज्य से संबंध रखता है, परन्तु राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का प्रयास नहीं करता; वह ''पूरी की पूरी राज-व्यवस्था पर शासन'' करने का प्रयास नहीं करता।

चौथे, नागरिक समाज के दायरे में बहुवाद और वैविध्य भी आता है। इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, सूचनात्मक व शैक्षणिक हित समूह, विकासात्मक, विषयोन्मुखी एवं नागर समूहों सहित, औपारिक व अनौपचारिक संगठनों का एक विस्तृत क्षेत्र आता है। इसके अतिरिक्त, नागरिक समाज में वो भी आता है, जिसे थॉमस मेत्ज़र ''वैचारिक पण्यक्षेत्र'' (ideolgical marketplace) कहते हैं, यथा सूचना व विचारों का प्रवाह, जिसमें वो शामिल हैं जो राज्य का मूल्यांकन और आलोचना करते हैं।

पाँचवे, चौथे से यह बात सामने आती है कि नागरिक समाज किसी व्यक्ति अथवा समुदाय की सम्पूर्ण हित-शृंखला का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास नहीं करता। इसकी बजाय भिन्न-भिन्न समूह भिन्न-भिन्न हित-पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा उनको अपने दायरे में लाते हैं।

छठे, नागरिक समाज को नागरिक समुदाय की अधिक स्पष्ट रूप से लोकतंत्र को बढ़ावा देती दृष्य-घटना से अलग समझा जाना चाहिए। डायमण्ड का तर्क है कि नागरिक समुदाय नागरिक समाज के मुकाबले एक अधिक विस्तृत और अधिक संकीर्ण संकल्पना दोनों हैः अधिक विस्तृत इस लिहाज से कि इसमें संस्थाओं के सभी प्रकार (संकुचित समेत) आते हैं; अधिक संकीर्ण इस लिहाज से कि इसमें सिर्फ दायित्वों के इर्द-गिर्द समतल रूप से संरचित संस्थाएँ ही होती हैं जो कि कमोबेष अन्योन्य, सहकारी, सम्मित और विष्वासपूर्ण होती हैं।

बोध प्रष्न 3

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग करें।

ii) अपने उत्तरों के सुझावों के लिये इकाई का अंत देखें।

1) नागरिक समाज और समुदाय के बीच अंतर विषयक फर्डीनैंड टोनीस के क्या विचार हैं?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) नागरिक समाज के मूल लक्षणों का ब्यौरेवार विवरण दें और वर्णन करें।

.....

.....

.....

.....

13.4 सारांष

नागरिक समाज, जिसका मूल हालाँकि लॉकियन परम्परा में है, ने बीसवीं सदी में जाकर लोकप्रियता हासिल की, जो कि पूर्व-यूरोपीय समाजवादी शासन की समाप्ति के आलोक में हुआ।

लॉक से परे, पूर्ववर्ती विचारक जिन्होंने नागरिक-समाज संबंधी धारणा के विकास में योगदान दिया, वे थे – टॉकवि, हेगेल और मार्क्स। मार्क्सवादी दृष्टिकोण को और अधिक विस्तार देते हुए हेगेल ने इसको एक भिन्न परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया।

नागरिक समाज को ऐसे कुछ लक्षणों के ब्यौरेवार विवरण के शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है जो कि आप इस इकाई में पढ़ चुके हैं।

एक ओर नागरिक समाज के बीच संबंधों और दूसरी ओर राज्य, लोकतंत्र और समुदाय की भी चर्चा की गई है।

13.5 कुछ उपयोगी पुस्तकें

चंधोक, एन., *स्टेट एंड सिविल सोसायिटी*, नई दिल्ली : सेज, 1995

कोहेन, जे. और अरैटो, *ए. सिविल सोसायिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी*, कैम्ब्रिज : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रैस, 1992

हेंस, जैफ., *डैमोक्रैसी एंड सिविल सोसायिटी इन द थर्ड वर्ल्ड*, क्रैम्ब्रिज : पॉलिसी प्रेस, 1997

13.6 बोध प्रष्नों के उत्तर

बोध प्रष्न 1

1) देखें भाग 13.2

2) देखें भाग 13.2

बोध प्रष्न 2

1) देखें उपभाग 13.2.2

2) देखें उपभाग 13.2.2

बोध प्रष्न 3

1) देखें उपभाग 13.2.3

2) देखें भाग 13.3